भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *266 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

अंतदेर्शीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही

*266. **श्री दिलीप शइकीया :**
श्रीमती साजदा अहमद :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और क्या पिछले दस वर्षों के दौरान इसमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) देशभर में माल की आवाजाही तीव्र हो सके, इसके लिए अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) असम सहित देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में जलमार्गों के माध्यम से माल/ कार्गो की अवाजाही के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही विकास परियोजनाएं क्या हैं और पिछले दस वर्षों के दौरान कितने नए जलमार्ग जोड़े गए हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, लागत और धनराशि के अब तक किए गए कुल आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“अंतदेर्शीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही” के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री दिलीप शइकीया एवं श्रीमती साजदा अहमद द्वारा पूछे गए दिनांक 13.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *266 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक में संदर्भित विवरण

(क): पिछले दस वर्षों के दौरान अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल-भाड़ा परिवहन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही 2013-14 के 18.10 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 133.03 मिलियन टन हो गई है, जो 22.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज करती है। प्रचालनरत राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2014 में 5 से बढ़कर 2024 में 26 हो गई है।

(ख): अंतर्देशीय जल संपर्कता बढ़ाने के संबंध में अवसंरचना और नीतिगत उपायों के जरिए राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध-1** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): असम सहित देश के पूर्वोत्तर राज्यों में जलमार्गों के माध्यम से माल-भाड़ा/कार्गो परिवहन के क्षेत्र में शुरू की गई प्रमुख विकास परियोजनाओं, कुल निधि आबंटन, व्यय की गई लागत और वर्तमान स्थिति का विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के अंतर्गत स्वीकृत/शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-3** में दिया गया है। वर्ष 2016 तक देश में 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। 2016 में, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के माध्यम से 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़े गए, जिससे राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई। वर्ष 2016 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल एक राष्ट्रीय जलमार्ग था। वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं।

अनुबंध-1

अवसंरचना और नीतिगत उपायों को दर्शाते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:

(क) अवसंरचना उपाय:

(i) जलयानों के प्रचालन के लिए 35/45 मीटर चौड़ाई और 2.0 / 2.2 / 2.5 / 3.0 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) का नौचालन चैनल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) में फेयरवे रखरखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रखरखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और नियमित जलीय सर्वेक्षण) किए जाते हैं।

(ii) रा.ज.-1 (गंगा नदी) पर 49 सामुदायिक जेट्टियों, 20 फ्लोटिंग टर्मिनलों, 3 मल्टी-मोडल टर्मिनलों (एमएमटी) और 1 इंटर-मोडल टर्मिनल (आईएमटी) का निर्माण किया गया है।

(iii) पांडु में एक एमएमटी और जोगीघोपा, बोगीबील और धुबरी में स्थायी टर्मिनलों के साथ ही रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) पर 12 फ्लोटिंग टर्मिनल उपलब्ध कराए गए हैं। 7.09 करोड़ रु. के निवेश से जोगीघोपा, पांडु, बिश्वनाथ घाट और नेमाती में चार समर्पित पर्यटक जेट्टियां उपलब्ध कराई गई हैं। उपरोक्त के अलावा, असम में सदिया, लायका और ओरियम घाट के लिए क्रूज और यात्रियों हेतु जेट्टियों का निर्माण किया गया है।

(iv) रा.ज.-3 (केरल में पश्चिमी तट नहर) पर गोदामों के साथ 9 स्थायी अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और 2 रो-रो/रो-पैक्स टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(v) गोवा सरकार को वर्ष 2020 में 3 फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टियां और सितंबर 2022 के दौरान 1 जेट्टी उपलब्ध की गई तथा मंडोवी नदी (रा.ज.-68) में स्थापित की गई। आंध्र प्रदेश में रा.ज.-4 (कृष्णा नदी) के हिस्से पर 4 पर्यटक जेट्टियां, उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन जलखंड में रा.ज.-110 (यमुना नदी) पर 12 फ्लोटिंग जेट्टियां और रा.ज.-73 (नर्मदा नदी) पर 2 जेट्टियां चालू कर दी गई हैं। बिहार में रा.ज.-37 (गंडक नदी) पर 2 जेट्टियों के निर्माण के लिए निविदा सौंपी गई है।

(ख) नीतिगत उपाय:

- कार्गो मालिकों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 35% प्रोत्साहन प्रदान करने और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल होते हुए रा.ज.-1, रा.ज.-2 और रा.ज.-16 पर कार्गो आवाजाही के लिए निर्धारित सेवा स्थापित करने संबंधी योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस योजना से 800 मिलियन टन किमी कार्गो को आईडब्ल्यूटी मोड पर परिवर्तित करने की उम्मीद है, जो रा.ज. पर मौजूदा 4700 मिलियन टन किमी कार्गो का लगभग 17% है। यह योजना तीन वर्षों के लिए 100 करोड़ रु. से कम की लागत की है और योजना की सफलता के आधार पर इसे बढ़ाया या संशोधित किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष प्रभाव हेतु तथा जलमार्ग आवाजाही में कार्गो मूवर्स/स्वामियों का विश्वास बढ़ाने के लिए भारतीय नौवहन

निगम के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई जलयानों का उपयोग करके कोलकाता और वाराणसी/पांडु के बीच एक निर्धारित जलमार्ग कार्गो सेवा शुरू करना है।

- पीएसयू द्वारा कार्गो का स्थानांतरण: कार्गो को जलमार्गों पर मोडल शिफ्ट करने के लिए, 140 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से अंतर्देशीय जल परिवहन साधन का उपयोग करके अपने आवागमन की योजना तैयार करने के लिए संपर्क किया गया है। उनसे जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही की उनकी वर्तमान स्थिति की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्गो के मोडल शिफ्ट (स्थानांतरण) की योजना बनाने का आग्रह किया गया है। पीएनजी, सहकारिता/उर्वरक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारी उद्योग, इस्पात और कोयला मंत्रालय से आग्रह किया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पीएसयू को परामर्श दें कि वे यथासंभव आईडब्ल्यूटी मोड का उपयोग करें तथा एमआईवी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आईडब्ल्यूटी के लिए अपने कार्गो का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करें।

- पत्तनों के साथ एकीकरण: दुनिया भर में, जलमार्गों का सबसे बेहतर उपयोग तब होता है जब उन्हें पत्तनों से जोड़ा जाता है। कोलकाता पत्तन रा.ज.1 के साथ निर्बाध एकीकरण का अवसर प्रदान करता है और मल्टी मोडैलिटी की समस्या को हल करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता से वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया में मल्टीमोडल टर्मिनलों और कालूघाट में इंटरमोडल टर्मिनल के साथ-साथ रा.ज.-1 पर अन्य टर्मिनलों के प्रचालन और प्रबंधन के लिए अनुरोध किया गया है।

- कार्गो एकीकरण: जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही मल्टीमोडलिटी की समस्याओं से ग्रस्त है क्योंकि जलमार्गों के किनारे उद्योगों की कमी है। इसलिए, वाराणसी में कार्गो एकीकरण हब - फ्रेट विलेज और साहिबगंज में एकीकृत क्लस्टर-सह-लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम, एनएचएलएमएल को इन एमएमएलपी के विकास के लिए काम पर लगाया गया है। तीन एमएमटी के लिए रेल संपर्कता का काम मेसर्स इंडियन पोर्ट एंड रेल कंपनी लिमिटेड (एमओपीएसडब्ल्यू के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम) को सौंपा गया है।

- नदी क्रूज पर्यटन: नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज संचालकों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं। उनसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर, आईडब्ल्यूएआई टर्मिनलों पर तटीय बिजली का प्रावधान, अतिरिक्त बर्थिंग व्यवस्था आदि जैसे कदम उठाए गए हैं। प्रचालनरत करने के लिए नए क्रूज सर्किटों की पहचान की गई है। क्रूज आवागमन के लिए कुल 34 जलमार्गों की पहचान की गई है और 10 को पहले ही प्रचालनरत कर दिया गया है।

- आईबीपी मार्ग: मइया और सुल्तानगंज के बीच भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 5 और 6 को सफल परीक्षण आवागमनों के साथ हाल ही में प्रचालनरत किया गया है।

अनुबंध-2

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईडब्ल्यूएआई द्वारा शुरू की गई बड़ी विकास परियोजनाएं

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में.)	किया गया व्यय (करोड़ रु. में.)	स्थिति
1	2020-21 से 2024-25 तक रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) का समग्र विकास	474.00	405.17	85%
2	पांडु पत्तन टर्मिनल से एनएच-27 तक संपर्क (एप्रोच) मार्ग का विकास और रा.ज.-2 पर पांडु, गुवाहाटी (असम) में पत्तन मरम्मत सुविधा का विकास	388.00	259.44	67%
3	2020-21 से 2024-25 तक रा.ज.-16 (बराक नदी) का समग्र विकास	148.00	37.05	25%
	कुल	1010.00	701.66	

अनुबंध-3

क्र.सं.	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के अंतर्गत योजनाएं	लागत (करोड़ रु. में)
क	**असम**	
1	विभिन्न क्षमताओं के यात्री जलयानों का निर्माण, टर्मिनल सुविधाओं का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी रा.ज.-2 व बराक रा.ज.-16 पर आईडब्ल्यूटी, असम के चालकदलों का क्षमता निर्माण	25.00
ख	**मिजोरम**	
1	त्लांग नदी में आईडब्ल्यूटी के विकास के लिए डीपीआर की तैयारी	0.89
2	छिमतुईपुई में आईडब्ल्यूटी के विकास के लिए डीपीआर की तैयारी	1.41
ग	**नागालैंड**	
1	केन्दीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत नागालैंड में नोउने तथा शिलोई झील में जल क्रीड़ाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीपीआर की तैयारी	0.90
2	दोयांग झील में आईडब्ल्यूटी के विकास के लिए डीपीआर तैयार करने का प्रस्ताव	0.85
ध	त्रिपुरा	
1	गुमती नदी का विकास करके बांग्लादेश में मेघना नदी प्रणाली के साथ लिंकेज स्थापित करना।	24.53
	कुल	53.58

*****